



सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु

सिद्धार्थनगर-272202 उप्र० (भारत)

Email Id: registrar@suksn.edu.in, Website : www.suksn.edu.in

पत्रांक-1370 कु0स0का0 / सि0वि0वि0 / 2026

दिनांक- 16-01-2026

सेवामें,

1. अधिष्ठाता, समस्त संकाय,
2. प्राचार्य/प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।

विषय :- भारतीय उच्च शिक्षा के अन्तर्राष्ट्रीयकरण और शैक्षणिक गुणवत्ता और वैश्विक अनुभव को बढ़ाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्रांक संख्या-भा.स.-67 / सत्तर-1-2025 दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या-13-14 / 2020 (Part-I)-ICC दिनांक 23-12-2025 के अनुसार Erasmus+Programme के अन्तर्गत भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए विभिन्न अवसरों की जानकारी दी गयी है।

Erasmus+Programme यूरोपीय संघ की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य यूरोप एवं भागीदारी देशों (जिसमें भारत भी सम्मिलित है) के उच्च शिक्षा संस्थानों के मध्य शैक्षणिक सहयोग को सुदृढ़ करना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रमुख घटक संचालित किये जाते हैं—

- International Credit Mobility (ICM)
- Erasmus Mundus Joint Masters (EMJM)
- Capacity Building For Higher Education (CBHE)
- Jean Monnet Activities (JMA)

संलग्न पत्र में की गयी अपेक्षानुसार निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही कराते हुए समय-समय पर कृत कार्यवाही से शासन को अवगत भी कराने के निर्देश प्रदान किये गये हैं—

अतः उपरोक्त के संदर्भ में संलग्न पत्र के अनुसार अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही कराते हुए कृत कार्यवाही की सूचना से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक— यथोपरि।

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु
सिद्धार्थनगर।

पत्रांक— / तददिनांकित।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, कुलपति को मा० कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. सम्बन्धित पत्रावली हेतु।

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु
सिद्धार्थनगर।

संख्या-आ-अ-67/सतर-1-2025

प्रेषक,

शक्ति अहमद सिंदीकी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- निदेशक,
उच्च शिक्षा,
प्रयागराज, 20प्र०।
- 2- कुलसचिव,
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
20प्र०।

उच्च शिक्षा अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: ८/ दिसम्बर, 2025

विषय:- भारतीय उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण और शैक्षणिक गुणवत्ता और वैश्विक अनुभव को बढ़ाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्र संख्या-13-14/2020(Pvt-I)-1CC दिनांक 23-12-2025 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से Erasmus+ programme के अन्तर्गत भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए विभिन्न अवसरों की जानकारी दी गई है।

2- Erasmus+ programme यूरोपीय संघ की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य यूरोप एवं आगीदार देशों (जिसमें भारत भी सम्मिलित हैं) के उच्च शिक्षा संस्थानों के मध्य शैक्षणिक सहयोग को सुदृढ़ करना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रमुख घटक संचालित किये जाते हैं :-

- International Credit Mobility (ICM)
- Erasmus Mundus Joint Masters (EMJM)
- Capacity Building for Higher Education (CBHE)
- Jean Monnet Activities (JMA)

उक्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत छात्र एवं संकाय गतिशीलता, संयुक्त डिग्री/मास्टर्स कार्यक्रम, पाठ्यक्रम विकास, संस्थागत सुधार, शासन एवं अकादमिक गुणवत्ता संवर्धन से संबंधित परियोजनाओं हेतु हर वर्ष नवम्बर-दिसम्बर में call for proposals आमंत्रित किए जाते हैं।

3- इस ऐरेन्टी में मुझे यह कहने का लिदेश हुआ है कि कृपया संलग्न पत्र में की गयी अपेक्षानुसार निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए समय-समय पर कृत कार्यवाही से शासन को अवगत भी कराने का काम करें :-

- (1) अपने विश्वविद्यालय/संस्थानों में Erasmus+ programme के अन्तर्गत उपलब्ध अवसरों की पहचान करें।
- (2) यूरोपीय उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ अंकादमिक एवं संस्थागत सहयोग की सम्भावनाओं का अन्वेषण करें।
- (3) छात्र एवं संकाय भौमिकी, संयुक्त मास्टर्स प्रोग्राम, क्षमता निर्माण परियोजनाओं आदि हेतु प्रस्ताव तैयार कर संबंधित Erasmus+ action के अन्तर्गत आयोजन सुनिश्चित करें।
- (4) इस उद्देश्य हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर एक Erasmus+ नोडल अधिकारी/अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्रकोष्ठ को क्रियाशील करें।
- (5) प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा Erasmus+ programme के अन्तर्गत की गई कार्यवाही की मासिक प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से उच्च शिक्षा विभाग को प्रेषित की जायेगी।
- (6) मासिक प्रगति रिपोर्ट संलग्नक-1 में दिये गये निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 10 तारीख तक ई-मेल एवं भौतिक रूप से भी उच्च शिक्षा विभाग, उत्तरांशासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय,

Digitally signed by

SHAKIL AHMAD SIDDIQUI

(शकील अहमद सिद्दीकी)

12:03:16

संयुक्त सचिव

राजीव कुमार सिंह
फोन: 011-23553501, 011-235503
ईमेल: iccell@nic.in

राजीव कुमार सिंह
राजीव कुमार सिंह ने दिल्ली-110 001
127 टीवी एवं शशि शर्मा, नई दिल्ली-110 001

No.13-14/2020(PartI)-ICC

Date: 23rd December, 2025

Dear Ma'am/ Sir,

राजीव कुमार सिंह 67 / दिसंबर-2025

I would like to draw your kind attention to the Erasmus+ Programme, which is the flagship initiative of the European Union, aimed at strengthening collaboration between higher education institutions worldwide. Erasmus+ provides structured opportunities for student and academic mobility, capacity building, and institutional partnerships with universities across EU member states and partner countries - including India.

2. Every year during November-December, Erasmus+ announces the opening of 'Call for Proposals' for partner countries offering individual scholarships and institutional collaboration opportunities through four programmes, namely, (i) International Credit Mobility (ICM), which supports short and long-term student and staff mobility between European and partner-country institutions, (ii) Erasmus+ Master Joint Masters (EMJML) program, offering fully funded one or two-year high-quality master's programmes delivered by the Erasmus+ Universities consortia, (iii) Capacity Building for Higher Education (CBHE), supporting 2-4 year projects focused on curriculum development, institutional reform, and governance improvement and (iv) Jean Monnet Activities (JMA), promoting teaching and research on European Union studies through Modules, Chairs, and Centres of Excellence. 2-pager information brochure on these programs are attached for reference. Call for proposals for all these Erasmus+ programs are closing in early/mid February 2026.

2. I would like to add that during recent high-level meetings the European Union has shown keen interest in expanding the educational collaboration with India in the light of the evolving higher education landscape in the country. In order to take forward the potential collaboration we have recently designated an Erasmus+ National Focal Point (ENFP), details of which are as under:

2084/5(A) Name: Mr. Rajeev Kumar Sinha, Under Secretary (ICC), MoE.

504 Email: iccell.edu@nic.in, rajeevk.sinha@nic.in

4. I would urge you to encourage Universities under your administrative control to explore active participation in Erasmus+ initiatives, by strengthening collaborations with European higher education institutions, (अंतर्राष्ट्रीय सम्पर्कों) promoting mobility of students and academic staff, and submitting quality proposals under relevant Erasmus+ actions. Such engagement will contribute to the internationalisation of Indian higher education and enhancement of academic quality and global exposure.

लेटर लेटर
राजीव कुमार सिंह

5. We are planning to schedule an 'Online Information Session' on potential opportunities under Erasmus+, in partnership with the Erasmus+ team in early January 2026, details on which would be shared by the designated ENFP soon. I would appreciate if you disseminate this information widely within institutions under your jurisdiction and take suitable steps to leverage the opportunities available under the Erasmus+ Programme. Please feel free to contact ENFP for any further information / clarification on the Erasmus+ program.

With regards,

Yours sincerely

25/12/2025
(Dr. Vineet Joshi)

To

1. The Chief Secretaries of State Governments (as per attached list) for circulation among State Universities
2. Secretary (UGC) for circulation to all VCs of Central and Deemed to be Universities
3. Chairman (AICTE) for circulation to all IITs/NITs/IITs
4. CFTIs / IIISERs (as per attached list)

Erasmus+ Programme Jean Monnet Action for higher education

**Stimulating teaching and research on the European Union and foster dialogue
between academics and decision-makers in the EU and around the world**

What is Erasmus+?

For over 30 years, Europe has funded the Erasmus programme, which has enabled over four million European students to study, train, and gain experience abroad.

Erasmus+ recognises the importance of opening up these opportunities, funding exchange of students, academics, ideas and good practices between organisations in Programme Countries¹ and Partner Countries² throughout the world.

These global activities cover Higher Education (HE), Vocational Education and Training (VET), Youth and Sport.

What are Jean Monnet Actions?

The Jean Monnet Actions for higher education aim at promoting excellence worldwide in teaching and research in the field of European Union studies. These Actions also aim at fostering dialogue between the academic world and policy-makers, in particular with the aim of enhancing governance of EU policies.

'European Union studies' means the study of Europe in its entirety, with particular emphasis on the EU dimension, from an internal but also from a global perspective.

European Union studies cover the role of the EU in a globalised world and in promoting active European citizenship and dialogue between people and cultures.

Jean Monnet is expected to bring positive and long-lasting effects to the participants involved, to the promoting organisations, and to the policy systems within which they are framed.

Which Actions are supported?

Teaching and research activities:

New introductory or advanced teaching programmes or courses designed to be embedded in the official curriculum of a higher education institution.

- A **Jean Monnet Module** is a short teaching programme or course in the field of European Union Studies at a higher education institute. Each Module lasts three years with a minimum duration of 40 teaching hours per academic year. Modules may concentrate on one particular discipline in European studies or be multidisciplinary in approach.
- A **Jean Monnet Chair** is a teaching post with a specialisation in European Union Studies for university professors for duration of three years. The position is held by only one professor, who provides the

¹ EU member states and third countries associated to the Programme.

² Third countries not associated to the Programme.

minimum of 90 teaching hours per academic year. The Chair may also have a team to support and enhance the activities of the Chair, including the provision of additional teaching hours.

- **Centre of Excellence** is a hub or focal point of competence and knowledge on European Union subjects with project duration of three years. The Centre has a major role in reaching out to students from faculties not normally dealing with European Union issues as well as to policy makers, civil servants, organised civil society and the general public. The requirement to hold a Chair in order to set up a Centre of Excellence is removed.

Jean Monnet policy debate

Large thematic networks in Higher Education (one network on internal EU issues and one network on foreign policy issues addressing one specific priority will be supported each year) will have as primary objective to collect, share and discuss among the partners research findings, content of courses and experiences, products (studies, articles, etc.). Each network will establish a tool allowing the partners to share their academic works and run peer review exercises, also commenting on the posted documents.

Who can apply and take part in Jean Monnet actions? How?

Higher education institutions, organisations and associations around the world are eligible to apply for Jean Monnet actions. HEIs established in Programme Countries must hold a valid Erasmus Charter for Higher Education (ECHE). An ECHE is not required for participating HEIs in Partner Countries.

More information

Detailed information on the criteria and funding rules: [Erasmus+ Programme Guide](#)

Information on how to apply to annual calls for proposals is provided on the European Commission's Funding & Tender Opportunities portal: <https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home>

Jean Monnet mailbox: FACEA-AJM@ec.europa.eu

Erasmus+ Programme Capacity-building in the field of higher education (CBHE)

What is Erasmus+?

For over 30 years, Europe has funded the Erasmus programme, which has enabled over four million European students to study, train, and gain experience abroad.

Erasmus+ recognises the importance of opening up these opportunities, funding the exchange of students, academics, ideas and good practice between organisations in Programme countries¹ and Partner countries² throughout the world.

In the framework of the new programme 2021-2027, the international activities will cover Higher Education (HE), Vocational Education and Training (VET), Youth and Sport.

What is a CBHE project?

A Capacity Building for Higher Education project operates as a multilateral partnership between institutions active in the higher education field from Programme Countries and Partner Countries. Projects support the relevance, quality, modernisation and accessibility of higher education, to make it a driver for sustainable social and economic development.

All projects are required to pursue and observe the guiding principles of the action: inclusiveness, innovation, impact and sustainability.

What does a CBHE project do?

CBHE projects can carry out a range of activities focused on Partner Countries:

- Develop, test and adapt curricula, in terms of relevant and innovative content and through the teaching and learning methods used;
- Support university-enterprise cooperation;
- Work on upskilling and professionalisation of academic and administrative staff;
- Reform of the governance and management systems and structures at national, regional or institutional level;
- Foster the internationalisation of HEIs and their capacity to network effectively in research, scientific and technological innovation;
- Support the introduction of Bologna-type reforms at institutional, national or regional level;
- Develop and implement new approaches and tools for policy making and monitoring

Three types of projects:

1. FOSTERING ACCESS TO COOPERATION IN HIGHER EDUCATION:

These smaller scope projects are focused on higher education institutions. This project type is new and designed to cater for newcomers to the programme, less involved countries/regions, and for disadvantaged target groups. Project budget between EUR 200 000 and EUR 400 000, 2-3 years.

¹ EU Member States and third countries associated to the programme.

² Third countries not associated to the programme.

3. PARTNERSHIPS FOR TRANSFORMATION

These are also focused on higher education institutions and designed to have a larger and wider impact on innovation, university/business relations and institutional governance.

Project budget between EUR 400 000 and EUR 800 000, 2-3 years.

3. STRUCTURAL REFORM PROJECTS

These projects focus on the macro level of policy reforms required to foster internationalisation. Besides higher education institutions they will also require the involvement of education authorities and/or ministries. Project budget between EUR 800 000 and EUR 1 000 000, 3-4 years.

Who can apply and take part in Capacity-building in Higher Education? How?

Participation as an organisation:

Participation in CBHE projects is open to a range of stakeholders in the higher education sector:

Higher Education Institutions (HEIs)

- HEIs, associations or organisations of HEIs, as well as legally recognised national or international rector, teacher or student organisations;
- Bodies in charge of higher education (councils, agencies) and national authorities (ministries, departments of higher education) in partner countries for those projects supporting reform processes at national/regional level;
- Vectors of change in the education system (university managers, international departments, deans, quality agencies, etc.);
- Organisations and/or associations active in the labour market or in the fields of education, training or youth in partner countries.

Project partnerships

All projects must be based on a partnership of organisations from Programme Countries and from Partner Countries:

Minimum 4 organisations³

Minimum 1 HEI from 2 Programme Countries and 2 HEIs from one or more Partner Countries.

The number of organisations from Programme countries should not be higher than the number of organisations from Partner countries

Who can apply?

- HEIs, associations or organisations of HEIs, as well as legally recognised national or international rector, teacher or student organisations, established in a Programme Country or in one of the eligible Partner Countries³. The applicant institution applies on behalf of all participating organisations involved in the project.

How to apply

- **Funding opportunities for 2021-2027 and information on how to apply are announced on the European Commission's Funding & Tender Opportunities portal:**
<https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home>

What is new in 2021-2027?

- New structure for projects – three categories based on size and scope.

More Information

- Detailed information on the criteria and funding rules: **Erasmus+ Programme Guide**

³ Countries belonging to the following regions: Western Balkans, Neighboring and East Europe; Mediterranean, Russian Federation, Asia, Central Asia, Middle East, Pacific Sub-Region, Africa, Latin America, Caribbean. Partnership is not possible from 146 countries in Asia, 145 in East and the Pacific. For more information about the regions, see the [Programme Guide](#).

Erasmus+ Programme International credit mobility

What is Erasmus+?

For over 30 years, Europe has funded the Erasmus programme, which has enabled over four million European students to study, train, and gain experience abroad.

Erasmus+ recognises the importance of opening up these opportunities, funding exchange of students, academics, ideas and good practice between Programme countries¹ and Partner countries² throughout the world.

In the framework of the new programme 2021-2027, the international activities will cover Higher Education (HE), Vocational Education and Training (VET), Youth and Sport.

What is an International credit mobility project?

International credit mobility (ICM) supports the mobility of individuals in higher education institutions (HEIs), between Programme countries and Partner countries. Through ICM, European HEIs can set up mobility agreements with partners around the world³ to send and receive students and staff.

What does an ICM project do?

The activities supported in ICM are:

Student mobility: can be carried out in any study field and cycle (short cycle/bachelor/master/doctoral), and is open to recent graduates. The physical mobility can last from 2 to 12 months or between 5 and 30 days if part of blended mobility⁴. Student mobility can take the form of:

- A study period abroad at a partner HEI,
- A traineeship (work placement, internship) abroad in an enterprise, a research institute, a laboratory, an organisation or any other relevant workplace.

The two types of student mobility could be combined, if the total duration of the mobility period does not exceed the maximum of 12 months per study cycle.

Staff mobility: can be carried out by any type of higher education staff or by invited staff from outside the HEIs. The mobility period can last from 5 days to 2 months. It can take the form of:

- A teaching period for academic staff and for invited staff from non-academic organisations to teach at a partner HEI abroad,
- A training period for teaching and non-teaching staff in the form of training events abroad (excluding conferences), job shadowing, observation periods and/or training at a partner HEI.

A staff mobility period abroad can combine teaching and training activities. Any teaching or training period abroad may be carried out as a blended mobility.

¹ EU member states and third countries associated to the Programme.

² Third countries not associated to the Programme.

³ With the exception of Andorra, Faroe Islands, Monaco, San Marino, Switzerland, Vatican City State and the United Kingdom.

⁴ Blended mobility is a combination of physical mobility with a virtual component facilitating a collaborative online learning exchange and teamwork.

How is it funded?

Each Erasmus+ National Agency (NA) established in a Programme Country has a budget to fund a number of mobility projects between HEIs in that Programme Country and those in Partner Countries. Institutions from Programme Countries can apply to their NA to organise projects with HEIs in one or more Partner Countries. The NA awards the successful HEIs a grant to cover the mobility of a number of students and staff. This grant will cover the cost of the individual and travel grants and include a portion for organisational support.

For Individuals

Student and staff participants may receive a different monthly or daily contribution to their expenses abroad depending on whether their mobility is incoming (to Europe) or outgoing (from Europe). In addition, each selected individual participant will get a travel contribution based on the distance between the sending and the receiving institutions.

For more information, see the [Programme guide](#).

For Institutions

The mobility project grant will include a contribution of EUR 500 per mobile participant in order to offset the costs to the institution of organising the mobility project.

Who can apply and take part in an ICM project? How?

Taking part as an organisation:

Only HEIs from Programme Countries may submit an application to manage a project for mobility between Programme and Partner Countries.

Once the project is selected for funding, in order for the mobility to happen, the European HEI must sign an inter-institutional agreement with a HEI in a Partner Country. Under this agreement, it can host or send students, doctoral candidates or staff from/to the Partner-Country HEI. In the agreement, the sending and receiving institutions agree on the range of courses open to visiting students and on the options for staff mobility. These agreements make sure that the sending institution will recognise the credits gained by its students for successfully completed activities abroad, which will contribute to the student's degree once they return. Programme-Country HEIs require an Erasmus Charter for Higher Education to apply and take part; by signing the inter-institutional agreement, Partner-Country HEIs agree to adhere to the Charter's principles.

Taking part as an individual:

Students and staff may contact their HEI's international relations office for more information about the application and selection process.

What is new in 2021-2027?

- Focus on simplification. The application form is designed to have a regional approach, which will translate into a more flexible budget management during implementation.
- Enhanced opportunities. In addition to the student exchange of 2 to 12 months, an option for shorter blended mobilities (5-30 days) is introduced, along with opening up to recent graduates, and providing a more flexible format for doctoral candidates.

More information

Detailed information on the criteria and funding rules: [Erasmus+ Programme Guide](#)

International credit mobility mailbox: EAC-NA-ICM@ec.europa.eu